खंड १ नंबर २ अप्रैल २०१७

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

आरआईएस ने अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया

राजदूत हरदीप एस पुरी
अध्यक्ष, आरआईएस

कूटनीति में चार दशकों के प्रतिष्ठित कैरियर के बाद राजदूत हरदीप एस पुरी को सामान्य निकाय का प्रेसीडेंट और आरआईएस की शासी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा (2002–2005) और न्यूयॉर्क (2009–2013) दोनों ही जगहों पर अपनी सेवाएं प्रदान कीं। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले महज कुछ भारतीयों में से एक हैं और वह इसकी आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र हस्ती हैं।

हम आरआईएस के अध्यक्ष के रूप में राजदूत हरदीप पुरी एस का स्वागत करते हैं।

प्रो. सुखमय चक्रवर्ती पर विशेष व्याख्यान

(बाएं से दाएं) प्रो. वाई. के. अलघ, कुलाधिपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात, प्रो. मनमोहन अग्रवाल, आरबीआई चेयर प्रोफेसर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम, डॉ. वी. एस. शेषाद्री, कार्यवाहक अध्यक्ष, आरआईएस, माननीय डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष, आरआईएस, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और प्रो. वी.आर. पंचमुखी, संस्थापक महानिदेशक, आरआईएस।

आरआईएस के संस्थापक उपाध्यक्ष प्रो. सुखमय चक्रवर्ती (1983–1990) को भारत के सबसे प्रशंसित विकास अर्थशास्त्रियों में शुमार किया जाता था। आर्थिक नियोजन और विकास के दर्शन एवं कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों में उनकी गहरी रुचि थी। वह भारतीय प्रधानमंत्रियों की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और उन्होंने लगातार तीन प्रधानमंत्रियों को अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। उन्होंने सत्तर के दशक के दौरान भारतीय योजना आयोग के एक सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं।

प्रो. चक्रवर्ती ने अपना जीवन ज्ञान के प्रसार के साथ–साथ अपनी शैक्षणिक प्रतिभा के जरिए आर्थिक नियोजन को एक उपयोगी प्रयोग बनाने में समर्पित कर दिया था। आरआईएस ने अपने प्रलेखन केंद्र (डॉक्यूमेंटेशन सेंटर) को प्रो. सुखमय चक्रवर्ती की स्मृति में समर्पित कर दिया है। इस अवसर पर 17 मार्च, 2017 को एक विशेष समारोह आयोजित किया गया जिसमें प्रो. मनमोहन अग्रवाल, आरबीआई चेयर प्रोफेसर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम ने प्रो. सुखमय चक्रवर्ती के जीवन और उत्कृष्टम कार्यों पर एक विशेष व्याख्यान दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं आरआईएस के पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉ. मनमोहन सिंह की गरिमामय उपस्थिति भी इस अवसर पर रही और उन्होंने सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रो. चक्रवर्ती एवं उनके बहुमूल्य कार्यों के बारे में अपनी श्रेष्ठ धारणा को स्मरण किया।

गुजरात स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति प्रो. वाई. के. अलघ और आरआईएस के संस्थापक महानिदेशक प्रो. वी.आर. पंचमुखी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास नियोजन प्रक्रिया में प्रो. सुखमय चक्रवर्ती के विशाल योगदान को स्मरण किया। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें आरआईएस के अनुसंधान संकाय के कुछ पूर्व सहयोगी भी शामिल थे।

डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक एजेवेडो ने आरआईएस के सत्र को संबोधित किया

विश्व व्यापार संगठन में कृषि और मत्स्य पालन से संबंधित वार्ताएं सदा ही भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं क्योंकि इसकी विशाल आबादी इन क्षेत्रों पर निर्भर है। आरआईएस इस तरह के विचार–विमर्श में सबसे आगे रहा है। अपने इन अथक प्रयासों के तहत आरआईएस ने नई दिल्ली में 9 फरवरी, 2017 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के महानिदेशक श्री रॉबर्टो एजेवेडो के साथ एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के आरंभिक संबोधन के साथ सत्र का शुभारंभ हुआ। डॉ. राम उपेंद्र दास, प्रोफेसर, आरआईएस, डॉ. मुकेश भटनागर, प्रोफेसर एवं डॉ. सचिन कुमार शर्मा, सहायक प्रोफेसर (ये दोनों ही डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की ओर से), डा. रानजा सेनगुप्ता, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क, डॉ. अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय सह–संयोजक, एसजेएम, सुश्री दीपा सिन्हा, भोजन के अधिकार का अभियान , श्री युद्धवीर सिंह, महासचिव, किसान आंदोलन की अखिल भारतीय समन्वय समिति, डॉ. विजू कृष्णन, संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा ने भारत एवं अन्य विकासशील देशों से संबंधित डब्ल्यूटीओ मुद्दों पर अपने–अपने संक्षिप्त विचार पेश किए। अपने जवाब में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने अनसुलझे मुद्दों पर आम सहमति कायम करने के लिए सदस्य देशों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाने का आह्वान किया।

(बाएं से चौथे) श्री रॉबर्टो एजेवेडो, महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन संवादात्मक सत्र में बोलते हुए।

एसडीजी पर मंत्रणाः सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) वाले वर्ष 2030 के सतत विकास एजेंडे में विकास के तीन आयामों अर्थात सामाजिक, आर्थिक और स्थायित्व को कवर किया गया है। भारत आर्थिक प्रगति, समावेश और स्थायित्व के कई क्षेत्रों में खुद के लिए पहले ही कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर चुका है। इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन के साथ–साथ एसडीजी के साथ तालमेल बैठाने में भी राज्य सरकारों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

पिछले कई महीनों के दौरान आरआईएस ने एसडीजी पर राष्ट्रीय स्तर की मंत्रणा आयोजित करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। इस श्रृंखला में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) ने आरआईएस और नीति आयोग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 23 फरवरी, 2017 को एसडीजी 7 – 'सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा' पर राष्ट्रीय स्तर की मंत्रणा का आयोजन किया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. अशोक कुमार जैन, सलाहकार (ग्रामीण विकास), नीति आयोग, डॉ. अनिल कुमार जैन, अपर सचिव, नीति आयोग, डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, डॉ. अजय माथुर, महानिदेशक, टेरी और श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने, एनडीसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि और ऊर्जा दक्षता पर चर्चाएं भी कार्यक्रम में शामिल थीं।

डॉ. अरविंद पनगढ़िया, उपाध्यक्ष, नीति आयोग मुख्य भाषण देते हुए।

नीली अर्थव्यवस्था पर उभरते परिपेक्ष्य: ब्लू इकोनॉमी मंच

नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) पर अपने अनुसंधान कार्यक्रम के तहत आरआईएस ने हिंद महासागर के लिए ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं ' पर भी एक व्यापक रिपोर्ट पेश की थी। आरआईएस वर्ष 2015 से ही 1.5 ट्रैक मोड के तहत 'आईओआरए' क्षेत्र के लिए ब्लू इकोनॉमी पर संवाद का संचालन कर रहा है। चूंकि ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधन भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आरआईएस का लक्ष्य ब्लू इकोनॉमी फोरम (बीईएफ) बनाकर अपने कार्यक्रम को समेकित करना है, ताकि अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करना, वाद–विवाद, अनुसंधान करना एवं जागरूकता बढ़ाना और शोध निष्कर्षों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना संभव हो सके। इस संबंध में आरआईएस ने 23 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में 'ब्लू इकोनॉमी पर उभरते परिप्रेक्ष्य' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अपने विचार पेश किए और आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी. एस. शेषाद्री ने इसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर *'ब्लू इकोनॉमी की संभावना को उन्मुक्त करना'* नामक संक्षिप्त नीतिगत पुस्तिका भी पेश की गई थी। आरआईएस के प्रोफेसर डॉ. एस.के. मोहंती ने हाल ही में आरआईएस में स्थापित किए गए ब्लू इकोनॉमी मंच (बीईएफ) के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी।

ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं को उन्मुक्त करने पर संक्षिप्त नीतिगत पुस्तिका पेश करते हुए।

कंपनियों की निर्यात संबंधी क्षमता में वित्तीय पहुंच और वित्तीय विकास की भूमिका

आरआईएस की ब्रेकफास्ट संगोष्ठी श्रंखला के तहत 'कंपनियों की निर्यात संबंधी क्षमता में वित्तीय पहुंच एवं वित्तीय विकास की भूमिका: एशिया–प्रशांत से अनुभवजन्य साक्ष्य' पर एक संगोष्ठी 3 जनवरी, 2017 का आरआईएस में आयोजन किया गया था। श्री टी.सी.ए. रंगनाथन, पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। आरआईएस स्थित आसियान इंडिया सेंटर के सलाहकार डॉ. दुरायराज कुमारसामी इस अवसर पर वक्ता थे और उन्होंने इस विषय पर अध्ययन का यह निष्कर्ष पेश किया कि 'वित्त और वित्तीय विकास तक पहुंच आखिरकार कैसे एशिया–प्रशांत देशों में कंपनियों की निर्यात करने संबंधी क्षमता को प्रभावित करती है।' 'विश्व बैंक उद्यम सर्वेक्षण' से प्राप्त कंपनी स्तर के आंकड़ों का उपयोग करने पर अध्ययन में यह पाया गया कि वित्त तक पहुंच इन कंपनियों की निर्यात करने की क्षमता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र में विकास होने से कंपनियों द्वारा निर्यात बाजार में कदम रखने की संभावना बढ़ जाती है। वित्तीय विकास का प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण है। अध्ययन में पाया गया कि वित्त तक पहुंच, वित्तीय विकास और स्थान विशेष का जो पारस्परिक प्रभाव पड़ता है उससे कंपनियों की निर्यात करने संबंधी क्षमता पर स्थान विशेष का नकारात्मक असर कम हो जाता है। अध्ययन से पता चला है कि वित्त तक पहुंच बढ़ने और वित्तीय विकास (बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच में वृद्धि) होने की स्थिति में राजधानी या मुख्य शहरों से दूर रह कर अपना परिचालन करने वाली कंपनियों को निर्यात बाजार में प्रवेश करने में आसानी होगी। अध्ययन में इस बात का समर्थन किया गया है कि वित्तीय विकास को मजबूत करने से कंपनियों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही अध्ययन में दूरस्थ स्थानों के लिए कंपनियों की निर्यात गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने हेतु वित्त तक पहुंच की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है।

वित्तीय पहुंच और वित्तीय विकास की भूमिका पर संगोष्ठी।

एशिया–प्रशांत व्यापार और निवेश रिपोर्ट

आरआईएस ने 16 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में *'एशिया–प्रशांत व्यापार और निवेश रिपोर्ट (एपीटीआईआर) 2016: मुख्य निष्कर्ष एवं क्षेत्र के लिए निहितार्थ* पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। विश्व व्यापार संगठन में भारत के पूर्व राजदूत जयंत दासगुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की। बैंकाक स्थित संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के व्यापार, निवेश और नवाचार प्रभाग की निदेशक डा. सुसान एफ. स्टोन मुख्य वक्ता थीं। उनकी प्रस्तुति के बाद एक खुली परिचर्चा आयोजित की गई।

(बाएं से सबसे पहले) डॉ. सुसान एफ. स्टोन, निदेशक, व्यापार, निवेश और नवाचार प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप, बैंकाक। विश्व व्यापार संगठन में भारत के पूर्व राजदूत जयंत दासगुप्ता संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए।

चाइनीज पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के प्रतिनिधिमंडल साथ संवाद

चाइनीज पीपुल्स इंस्टीटच्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (सीपीआईएफए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 21 फरवरी, 2017 को एक संवादात्मक सत्र के लिए आरआईएस का दौरा किया। चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में ये शामिल थे: चाइनीज पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (सीपीआईएफए) के कार्यकारी उपाध्यक्ष राजदूत लू शुमिन, सीपीआईएफए के उपाध्यक्ष राजदूत पेंग केयू, कोलकाता के पूर्व महावाणिज्य दूत श्री माओ सिवेई, सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज चाइना रिफॉर्म फोरम के निदेशक प्रोफेसर एम.ए. जियाली, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के दक्षिण एशिया अध्ययन के संपादकीय निदेशक श्री वाई.ई. हैइलिन, एशियाई, अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिकी मामलों के विभाग (सीपीआईएफए) की निदेशक सुश्री शेन जून, चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च एसोसिएट डा. जेग एइपिंग और सीपीआईएफए की स्टाफ सुश्री लिन मिनस्क्यू। विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की ओर से रिसर्च फेलो डॉ. संजीव कुमार उपस्थित थे। आरआईएस के प्रतिनिधिमंडल में ये शामिल थे: प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, डॉ. एस.के. मोहंती, प्रोफेसर, डॉ. राम उपेंद्र दास, प्रोफेसर, प्रो. टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, डा. टी.पी. राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, डॉ. बीना पांडे, रिसर्च एसोसिएट, डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, डॉ. प्रियदर्शी दास, रिसर्च एसोसिएट, डॉ. अमित कुमार, रिसर्च एसोसिएट और डॉ. सुशील कुमार, सलाहकार।

चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य संवादात्मक सत्र में भाग लेते हुए।

उभरता भारत 2030

सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय, आरआईएस, नीति आयोग और भारत एवं भूटान के लिए संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र ने 15–17 फरवरी, 2017 को पुणे में 'उभरता भारत 2030: सशक्त विकास लक्ष्यों के लिए रणनीतियां' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। परिचर्चाओं के विषयों में ये शामिल थे: गरीबी एवं विषमताएं, शिक्षा और महिला–पुरुष स्थिति, टिकाऊ शहर, नौकरियां एवं आर्थिक विकास, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने सत्र के दौरान 'लक्ष्यों के लिए साझेदारी' पर प्रस्तुति दी। विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता की पुनर्संरचना

एफआईडीसी की मासिक संगोष्ठी श्रंखला के तहत 22 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में 'पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता की पुनर्संरचनाः नए अवसर और चुनौतियां' विषय पर डॉ. एम्मा मौडस्ले की एक प्रस्तुति आयोजित की गई। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत संबोधन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। श्री दिनकर अस्थाना, संयुक्त सचिव (डीपीए– II), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने इसकी अध्यक्षता की।

(बाएं से) डा. एम्मा मौडस्ले संगोष्ठी को संबोधित करते हुए। श्री दिनकर अस्थाना, संयुक्त सचिव (डीपीए–II), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने बैठक की अध्यक्षता की।

डॉ. मौडस्ले ने पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता के अंतर्निहित घरेलू एवं बाह्य आधारों को समझाया और इसके साथ ही इस तथ्य की ओर संकेत किया कि संबंधित नीति निर्माण को 'गैर तर्कसंगत' प्रभावों से अछूता नहीं रखा जा सकता है। इस वक्ता के मुताबिक, उत्तर–दक्षिण विभाजन की होड़ दरअसल अपनी समस्तं विविधता में निजी क्षेत्र को शामिल करने के साथ–साथ सहायता संबंधी बहस का एक सकारात्मक आकलन भी है। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव का भी उल्लेख किया जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बजाय अब वित्त (निवेश बैंकिंग, बीमा, आर्बिट्रेज, परिसंपत्ति प्रबंधन, उद्यम पूंजी, मुद्रा व्यापार, इत्यादि) की ओर उन्मुख होती जा रही है। उन्होंने इस बदलाव को 'वित्तीयकरण' की संज्ञा प्रदान की है। 'वित्तीयकरण' के विभिन्न स्तरों की भी व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था और माइक्रोफाइनेंस के रूप में की गई। उन्होंने विभिन्न विषयों जैसे कि 'विदेशी सहायता' से 'विकास वित्त' की ओर कदम, वित्तीय हितों एवं संस्थानों की सूक्ष्म एवं वृहद परिधियों के बीच संबंध और द्विपक्षीय दानदाताओं के बीच रुझान पर परिचर्चाओं के जरिए फिलहाल गहराते वित्तीयकरण–विकास गठजोड़ के बारे में विस्तार से बताते हुए अपनी प्रस्तुति समाप्त की।

भारत–सिंगापुर सीईसीए रिपोर्ट

आरआईएस स्थित एआईसी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से 27 मार्च 2017 को नई दिल्ली में *'भारत–सिंगापुरः व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)'* रिपोर्ट जारी करने का कार्यक्रम आयोजित किया। सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने 'भारत–सिंगापुरः व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)' नामक एआईसी–आरआईएस रिपोर्ट जारी की, जिसे आरआईएस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. वी.एस. शेषाद्री ने लिखा है।

सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय *भारत–सिंगापुरः व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते सीईसीए* पर रिपोर्ट जारी करती हुईं।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री श्रीकांत सोमानी, सदस्य, सीआईआई राष्ट्रीय परिषद और चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, सोमानी सिरामिक्स लिमिटेड ने आरंभिक भाषण दिया। वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने विशेष भाषण दिया। राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने भी विशेष भाषण दिया। सिंगापुर उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त डॉ. एडमंड चिया और नास्कॉम के निदेशक श्री गगन सभरवाल ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया।

डॉ. वी.एस. शेषाद्री ने रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति दी। इस रिपोर्ट में सीईसीए और आसियान–भारत एफटीए के परिप्रेक्ष्य में भारत–सिंगापुर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर गौर किया गया है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ हैं। एआईसी के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र ने आसियान के लिए भारतीय मिशन, आसियान सचिवालय, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और इंडोनेशियाई विदेश मंत्रालय के सहयोग से 19 जनवरी 2017 को जकार्ता में भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। आसियान के लिए भारत के राजदूत सुरेश के. रेड्डी ने आरंभिक भाषण दिया। भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने मुख्य भाषण दिया। इंडोनेशिया के उप विदेश मंत्री श्री ए.एम. फचीर ने विशेष भाषण दिया। आसियान के उप महासचिव श्री वोंगथेप अर्थकईवल्वैंटी और वियतनाम के उप विदेश मंत्री श्री गुयेन क्योपक ड्जंग ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) राजदूत प्रीति सरन ने समापन भाषण दिया। डॉ. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आसियान के सभी सदस्य देशों ने अपने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को सम्मेलन के लिए नामित किया और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 100 प्रतिभागियों ने इस एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।

भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर आयोजित सम्मेलन में प्रतिभागी शिरकत करते हुए।

यह सम्मेलन 23–24 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में 'आसियान–भारत सांस्कृतिक संबंध : ऐतिहासिक और समकालीन आयाम' पर आयोजित किए गए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अनुवर्ती आयोजन था। दूसरा सम्मेलन इसके साथ ही आसियान–भारत वार्तालाप भागीदारी की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिहाज से पहला आयोजन था।

सम्मेलन को चार सत्रों में विभाजित किया गया था, ताकि जन संपर्कों एवं सांस्कृतिक संबंधों के जरिए आसियान–भारत सामरिक भागीदारी के मार्ग की उभरती चुनौतियों की पहचान करने के साथ–साथ आसियान समुदाय के ब्लूप्रिंटों के नजरिए से विभिन्न चुनौतियों से पार पाने के लिए उपयुक्त नीतिगत विकल्पों की भी पहचान की जा सके। सम्मेलन में उन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, विश्लेषण किया गया और फिर एकजुट किया गया जिनसे आसियान और भारत के बीच के सांस्कृतिक संबंधों को समझने में मदद मिलेगी।

सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के छात्रों के साथ बैठक

पुणे स्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 32 छात्रों के एक समूह ने 24 फरवरी, 2017 को एक संवादात्मक सत्र में भाग लेने के लिए आरआईएस का दौरा किया। समूह की अगुवाई एसएसआईएस के निदेशक डॉ. शिवाली लवाले ने की थी। प्रो.सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और डॉ. एस.के. मोहंती, प्रोफेसर, आरआईएस ने छात्रों के इस समूह को आरआईएस की अनुसंधान गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

आरआईएस संकाय के सदस्यों के साथ संवादात्मक सत्र का आयोजन।

'पारंपरिक चिकित्सा' पर मंत्रणा

आरआईएस ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर 19 जनवरी 2017 को 'व्यापार, मानक और आईपीआर सहित पारंपरिक चिकित्सा' से संबंधित मुद्दों पर एक रणनीति विकसित करने के लिए हितधारकों से मंत्रणा का आयोजन किया। मंत्रणा का उद्देश्य आईपीआर और अन्य नियामक उपायों सहित उन वैश्विक घटनाक्रमों पर नियमित चर्चा एवं निगरानी करने और रणनीतियां बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार करना था जिनसे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आईटीएम) की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसका एक अन्य उद्देश्य विश्व भर में आईटीएम तक पहुंच बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने एवं पारंपरिक चिकित्सा पर और अधिक शोध अध्ययन सुनिश्चित करने के तरीकों पर गहन चर्चा करना था। इसमें उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभागों एवं संगठनों और सिविल सोसायटी के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और आईटीएम उत्पादों के व्यापार के मार्ग में मौजूद तकनीकी बाधाओं के बारे में बताया। श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश के पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने और स्वास्थ्य के लिए इस ज्ञान का निरंतर उपयोग करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। आयुष मंत्रालय में सचिव श्री अजीत एम शरण ने अपने आरंभिक भाषण में पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच के मामले में लाभ साझा करने से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आईटीएम और अन्य पारंपरिक ज्ञान के विकास पर व्यापक विचार विकसित करने के लिए सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण को एकीकृत करने हेतु सार्थक बहस का आह्वान किया। आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अनिल कुमार गनेरीवाला ने योग के वैश्वीकरण के बारे में बताया और इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) में भारत का रुख तय करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। आयुष मंत्रालय में वैज्ञानिक–4 डॉ. गजाला जावेद ने आयुष प्रणालियों के वैश्वीकरण के साथ–साथ इन प्रणालियों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अवसरों से लाभ उठाने की राह में मौजूद चुनौतियों का अवलोकन पेश किया।

श्री अजीत एम. शरण, सचिव, आयुष मंत्रालय उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए।

यह कहा गया कि व्यापार, मानक, पारंपरिक ज्ञान और आईपीआर से संबंधित मुद्दों पर मंत्रालय को नियमित रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर एक फोरम बनाने की आवश्यकता है। मंत्रणा के दौरान भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर एक फोरम (एफआईटीएम) बनाने संबंधी आरआईएस के प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया गया। खुली चर्चा में भाग लेने वालों में डॉ. एच. पुरुषोत्तम, सीएमडी, एनआरडीसी, आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ, अनुसंधान संगठनों के निदेशक, आयुष मंत्रालय के सलाहकार, निदेशक एवं अन्य तकनीकी अधिकारी, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों के शिक्षाविद, उद्योग संगठनों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। प्रोफेसर टी. सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने अपने समापन संबोधन में यह प्रस्ताव रखा कि आरआईएस इस मंत्रणा के दौरान दिए गए विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय के समक्ष समुचित प्रस्ताव पेश करेगा।

बांग्लादेश में भारत के विकास सहयोग पर गोलमेज सम्मेलन

बांग्लादेश में भारत के विकास सहयोग पर एक गोलमेज सम्मेलन पीआरआईए, एफआईडीसी और ऑक्सफैम इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से 24 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डॉ. राजेश टंडन, संस्थापक–अध्यक्ष, पीआरआईए ने 'बांग्लादेश के साथ भारत के विकास सहयोगः मुख्य निष्कर्षों' पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की। श्री कास्तुव चक्रबर्ती, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, पीआरआईए ने इस अवसर पर प्रस्तुति दी। सम्मेलन में प्रमुख चर्चाकर्ता या प्रतिभागी ये थेः राजदूत पिनक रंजन चक्रबर्ती, प्रतिष्ठित फेलो, ओआरएफ एवं पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस। ऑक्सफैम इंडिया के निदेशक–नीति, अनुसंधान एवं अभियान डॉ. रानू भोगल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

नाइजीरियाई दक्षिण–दक्षिण एकजुटता मॉडल

आरआईएस ने 7 फरवरी, 2017 को 'नाइजीरियाई दक्षिण–दक्षिण एकजुटता मॉडलः संचालक शक्ति (ड्राइविंग फोर्स), प्रेरणा और विदेश नीति फोकस' के विषय पर मासिक ब्रेकफास्ट संगोष्ठी का आयोजन किया। डॉ. सैदु नासिरु सुलेमान, सलाहकार, आरआईएस ने इस विषय पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद खुली चर्चा हुई।

नाइजीरियाई दक्षिण–दक्षिण एकजुटता मॉडल पर संगोष्ठी का आयोजन।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर संवादात्मक सत्र

चाइना सेंटर फॉर कंटेम्परेरी वर्ल्ड स्टडीज (सीसीसीडब्ल्यूएस) के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संवादात्मक सत्र के लिए 22 मार्च, 2017 को यहां का दौरा किया। चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ये थेः डॉ. चाई शांगजिन, सीनियर रिसर्च फेलो, डा. वांग लियांग, डॉ. चेन यिंग, डॉ. वू हांग, एसोसिएट रिसर्च फेलो, डा. झोऊ यूयुन, काउंसलर, भारत में चीनी जनवादी गणराज्य का दूतावास। चर्चा का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स थिंक टैंक के सहयोग और आपसी हित के अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान करना था।

आरआईएस की ओर से प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, प्रो. एस.के. मोहंती, प्रो. राम उपेंद्र दास, डॉ. बीना पांडे और डॉ. सब्यसाची साहा उपस्थित थे। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल की सुविधा के लिए प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने आरआईएस के कार्यकलापों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इसके बाद आरआईएस के संकाय ने विशेषज्ञता और अनुसंधान वाले अपने व्यक्तिगत क्षेत्रों पर संक्षिप्त विवरण पेश किए। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल ने दोनों संस्थानों के बीच गहन अकादमिक सहयोग के हितों एवं अवसरों के परस्पर व्याप्त होने के साथ–साथ भावी संवादों की संभावनाओं की भी सराहना की।

ब्रिक्स से संबंधित कार्यकलापों और वर्ष 2017 में ब्रिक्स की चीनी अध्यक्षता के दौरान सहयोग के अवसरों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों महत्वपूर्ण थिंक टैंकों की यह बैठक विशेष अहमियत रखती है। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर आरआईएस ने ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2016 में आयोजित ब्रिक्स शैक्षणिक और सिविल सोसायटी फोरमों के कार्यक्रम एवं परिणामों से जुड़े विवरण साझा किए।

आरआईएस संकाय के सदस्यों के साथ चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मंत्रणा करते हुए।

सतत विकास के लिए जैव विविधता पर आम सहमति

आरआईएस ने नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सहयोग से 8–9 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में 'सतत विकास लक्ष्यः भारत के सतत विकास के लिए जैव विविधता संबंधी चिंताओं, पारिस्थितिकी मूल्यों और जलवायु से जुड़े लचीलेपन को एकीकृत करने पर राष्ट्रीय मंत्रणा' का आयोजन किया जिस दौरान एसडीजी 13, 14 और 15 पर फोकस किया गया।

एजेंडे में कई विषय शामिल थे जैसे कि एसडीजी 15 भूमि पर जीवन–स्थलीय पारिस्थितिकीय संरक्षण और मानव की भलाई, एसडीजी 14 पानी के नीचे जीवन–तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों का सतत प्रबंधन, एसडीजी 13 लचीलेपन का निर्माण एवं जलवायु परिवर्तन का मुकाबला तथा इसके प्रभाव, उप समूह की सिफारिशें और आगामी कदम। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और एसडीजी 13, 14 और 15 का अवलोकन पेश किया। प्रो. एस.के. मोहंती ने सिफारिशें पेश कीं और आगामी कदमों के बारे में भी बताया।

विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

भारत–बांग्लादेश बहु क्षेत्रीय सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आरआईएस ने कोलकाता स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज (मकायास), द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी (एनएमएमएल) और नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (आईजीएनसीए) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 23–24 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में भारत–बांग्लादेश बहु क्षेत्रीय सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। श्री एम. जे. अकबर, माननीय राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। श्री मोजामेल हक, सांसद, मुक्ति युद्ध मामलों के माननीय मंत्री, बांग्लादेश सरकार मुख्य अतिथि थे। श्री अरिंदम मुखर्जी, सचिव, सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान ने स्वागत भाषण दिया। सुश्री श्रीप्रिया रंगनाथन, संयुक्त सचिव (बीएम), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया।

भारत में बांग्लादेश के माननीय उच्चायुक्त श्री सईद मुआजेम अली और नई दिल्ली स्थित आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी 'भारत बांग्लादेश आर्थिक सहयोगः चुनौतियां और अवसर' पर आयोजित सत्र के अग्रणी वक्ताओं में से एक थे। भारत सरकार में माननीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने सत्र की अध्यक्षता की।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी सम्मेलन में बोलते हुए। इस अवसर पर उपस्थित हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीया वस्त्र मंत्री, भारत सरकार।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने भी समापन सत्र में 'आगे की राह' विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। न्यायमूर्ति ए. एच.एम. शम्सुद्दीन चौधरी, पूर्व न्यायाधीश, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सत्र की अध्यक्षता की। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि थे।

विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

भारत–अफ्रीका आर्थिक साझेदारी

भारत अफ्रीका के आर्थिक एकीकरण का समर्थन करता है। जहां एक ओर भारत सभी अफ्रीकी देशों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारत आम सार्वजनिक वस्तुएं बनाने के उद्देश्य से विभिन्न अफ्रीकी क्षेत्रीय निकायों के साथ भी मिलकर काम कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की पहुंच इन तक हो सके। अतः भारत इसे ध्यान में रखते हुए इकोवास, कोमेसा, और ईएएस के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहा है। इसके साथ ही भारत उन बाजार अवसरों से लाभ उठाने के लिए अफ्रीका के साथ भागीदारी करने की तैयारी में है जो अफ्रीकी विकास एवं अवसर अधिनियम (एजीओए) जैसे समझौतों के बल पर अफ्रीका के लिए उपलब्ध हैं। भारत किस तरह से उन अवसरों को बेहतरीन तरीके से हासिल करने में अफ्रीका की सहायता कर सकता है जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत उसके लिए उपलब्ध हैं? इस तरह के समझौते आखिरकार कैसे दीर्घकालिक द्विपक्षीय संस्थागत साझेदारी और कारोबारी गठबंधनों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? इन सवालों के साथ–साथ अन्य प्रश्नों पर भी 12वें सीआईआई एक्जिम बैंक सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया था।

नई दिल्ली में 10 मार्च, 2017 को एक्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआ. ईआई) के सहयोग से 'भारत–अफ्रीका आर्थिक साझेदारी' पर आयोजित 12वें सीआईआई–एक्जिम बैंक सम्मेलन में प्रो. राम उपेंद्र दास।

विज्ञान कूटनीति पर आईटेक कार्यक्रम

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस) के निदेशक प्रो. बलदेव राज उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए।

आरआईएस ने 'विज्ञान कूटनीति पर आईटेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम' का शुभारंभ किया जो 9–20 जनवरी, 2017 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ उद्घाटन सत्र की शुरुआत हुई। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस) के निदेशक प्रो. बलदेव राज ने उद्घाटन भाषण दिया। श्री दिनकर अस्थाना, संयुक्त सचिव (डीपीए प्प), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. साधना रेलिया, प्रमुख, (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने भी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। डॉ. अमित कुमार, रिसर्च एसोसिएट, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। 21 देशों के 32 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

विज्ञान कूटनीति पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम में ये विषय शामिल थे: संस्कृति और विज्ञान कूटनीति, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान और सेवाओं की तलाश में वैश्विक सहभागिता– एक भारतीय अनुभव, एसटीआई में दक्षिण–दक्षिण और उत्तर–दक्षिण व्याख्यान, विज्ञान कूटनीति और एसडीजी, क्षेत्रवार फोकसः स्वास्थ्य तनाव प्रबंधन, कृषि, विज्ञान कूटनीति और टीएफएम, भारत की विदेश नीति में दोहरे उपयोग वाला एसएंडटी, भारतीय विज्ञान कूटनीतिः कुछ परिवर्तनकारी लम्हे, एक विज्ञान पत्रकार की वृहद राय, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विज्ञान कूटनीति की भूमिका, नीली अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सीडीएम, दक्षिण में क्षमता निर्माण में विज्ञान कूटनीति की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय आरएंडडी ढांचा और विज्ञान कूटनीति, ग्रामीण नवाचार और विज्ञान कूटनीति, तकनीकों में सामंजस्य–अवसर और चुनौतियां, और विज्ञान कूटनीति का उपयोग करके एसएससी को मजबूत करना।

प्रतिभागियों को संबोधित करने वाले प्रमुख वक्ता ये थेः डॉ. टी. रामासामी, पूर्व सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, डॉ. शैलेश नायक, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं पूर्व सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. वी. सिद्धार्थ, भारत के प्रधानमंत्री

आरआईएस संकाय के सदस्यों के साथ विज्ञान कूटनीति पर आईटेक कार्यक्रम के प्रतिभागीगण।

की विज्ञान सलाहकार परिषद के पूर्व सचिव एवं एमेरिटस वैज्ञानिक, डीआरडीओ, डॉ. एच. पुरुषोत्तम, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी), डॉ. एस आर राव, सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, डॉ. एस.के. सक्सेना, निदेशक, भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद, डॉ. सचिन गोयल, वरिष्ठ सलाहकार, अंर्तनाद, प्रो. प्रणव एन देसाई, प्रोफेसर, विज्ञान नीति में अध्ययन के लिए केंद्र, जेएनयू, प्रो. आराधना अग्रवाल, कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, डेनमार्क, डॉ. प्रवीण अरोड़ा, प्रमुख, कोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, डॉ. राजेश्वरी रैना, प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर–राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान (एनआईएसटीएडीएस), डॉ. पल्लव बागला, विज्ञान संपादक, एनडीटीवी और स्तंभकार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विकास नीति पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आईटेक/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत 13 फरवरी, 2017 से लेकर 10 मार्च 2017 तक नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विकास नीति (आईईआईडीपी)' पर अपना वार्षिक प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। 24 देशों के 32 से ज्यादा प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में इन विषयों को शामिल किया गयाः बहुपक्षवाद, मेगा क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाएं एवं विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ढांचा और बहुपक्षवाद के लिए चुनौतियां, विकासशील देशों में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर समझौता, दक्षिण में आर्थिक सहयोग की एक धुरी के रूप में विकास समझौता, जी–20 का महत्व और वैश्विक वित्तींय ढांचे के मुद्दे, सेवाओं का व्यापार और गेट्स, वैश्विक शासन के संदर्भ में दक्षिण–दक्षिण सहयोग, 'एशिया–प्रशांत व्यापार एवं निवेश रिपोर्ट (एपीटीआईआर) 2016ः मुख्य निष्कर्ष और क्षेत्र के लिए निहितार्थ', डब्ल्यूटीओ में एंटी–डंपिंग और सब्सिडी से संबंधित मुद्दे, मेगा क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं का उभरता ढांचा, एजेंडा 2030 और एसडीजी को समझना, पेरिस जलवायु समझौता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एसडीजी को अपनाना एवं स्थायित्व की चुनौतियां, स्थायित्व सुनिश्चित करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सहयोग, विकासशील देशों में सांख्यिकी प्रणालियां और एसडीजी संकेतक, पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता की पुनर्संरचनाः नए अवसर और चुनौतियां, विकासशील देश एवं सतत ऊर्जा, भारत–अफ्रीका साझेदारी की उभरती गतिशीलता, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण, भारत–यूरोपीय संघ के संबंधः आगे की राह, विकासशील देश के नजरिए से जी–20 और ब्रिक्स को समझना, और भारत का ऊर्जा क्षेत्र।

अधिक जानकारी के लिए कृपया आरआईएस की वेबसाइट www.ris.org.in पर जाएं।

आरआईएस संकाय के सदस्यों के साथ आईईआईडीपी पर आईटेक कार्यक्रम के प्रतिभागीगण।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

- मौलाना अब्दुल कलामआजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज (मकायास) और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (आईएससीएस) द्वारा संयुक्त रूप से 4 जनवरी, 2017 को कोलकाता में 'भारत–अफगानिस्तानः वर्तमान संबंध एवं भावी दिशा' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैनल परिचर्चा में भाग लिया।

- बेंगलुरू में 7 जनवरी, 2017 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए 14वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) 2017 संगोष्ठी के दौरान 'ज्ञान के हस्तांतरण और नवाचार को प्रोत्साहन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका' सत्र में भाग लिया।

- भारत की वीएनआर तैयार करने के लिए नीति आयोग द्वारा 9 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई कार्यदल की बैठक में 'भारत के लिए एचएलपीएफ 2017 टेम्पलेट हेतु स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षाओं (वीएनआर)' पर एक प्रस्तुति दी।

- ब्राजील में 16 जनवरी 2017 को रियो डी जनेरियो के बिशप कैथोलिक विश्वविद्यालय (पीयूसी–रियो), अंतर्राष्ट्रीय संबंध सं. स्थान (आईआरआई/(पीयूसी–रियो) और ब्रिक्स पॉलिसी सेंटर द्वारा 'ब्राजील के दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर संवादः एमएंडई' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए संगोष्ठी में 'मूल्यांकन और एसडीजी' पर एक प्रस्तुति दी।

- ब्राजील में 17 जनवरी 2017 को रियो डी जनेरियो के बिशप कैथोलिक विश्वविद्यालय (पीयूसी–रियो), अंतर्राष्ट्रीय संबंध सं. स्थान (आईआरआई/(पीयूसी–रियो) और ब्रिक्स पॉलिसी सेंटर द्वारा 'ब्राजील के दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर संवादः एमएंडई' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए संगोष्ठी में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग के मात्रा निर्धारण' पर एक प्रस्तुति दी।

- भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योगमंत्रालय द्वारा 19 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग पर सचिवों के समूह के तहत व्यापार और निवेश पर आयोजित की गई बैठक में भाग लिया।

- विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान द्वारा 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित किए गए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत–अफ्रीका संबंधः नई आर्थिक वास्तविकता' पर एक प्रस्तुति दी।

- अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग नेटवर्क (एनआईडीसी), द एशिया फाउंडेशन (टीएएफ), थाईलैंड रिसर्च फंड (टीआरएफ), और थमसैट यूनिवर्सिटी द्वारा 26 जनवरी 2016 को थ. ाईलैंड के बैंकॉक में संयुक्त रूप से ' त्रिकोणीय सहयोगः सबक सीखा और भविष्य की संभावना' विषय पर आयोजित किए गए एनआईडीसी फोरम 2017 के दौरान 'प्रमुख देशों के दृष्टिकोण से टीआरसी' पर विशेष सत्र के पैनल में शामिल थे।

- नई दिल्ली में 9 फरवरी 2017 को 3आ. ईई, जीडीएन एवं कैंपबेल कोलेबोरेशन और प्रभाव आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल द्वारा 'भारत में गवर्नेंस और सेवा वितरण पर प्राप्त राष्ट्रीय एवं वैश्विक साक्ष्य से लाभ उठाने' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए आधे दिन के आयोजन में भाग लिया।

- अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू) और भारत की संसद द्वारा 18–19 फरवरी 2017 को इंदौर में 'सशक्त विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करनाः क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना और एसडीजी के लिए संसाधन' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया।

- सतत विकास एवं गवर्नेंस के लिए संस्थान (आईएसडीजी) और ओक्सफैम इंडिया द्वारा 20 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में 'विकास सहयोग का भविष्यः उभरते भारत के लिए नीतिगत प्राथमि. कता' पर संयुक्त रूप से आयोजित की गई राष्ट्रीय संगोष्ठी और मंत्रणा के दौरान 'विकास सहयोग के लिए वक. ालत और गठबंधन' पर समापन सत्र को संबोधित किया।

- नई दिल्ली में 20–21 फरवरी 2017 को 'भारत का उदय और विकास चुनौतियांः अमेरिका के लिए नीतिगत निहितार्थ' पर एस्पेन कांग्रेसनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 'भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक भूमिकाः विकास और गरीबी का संबंध और अमेरिकी नीति के प्रति इसकी प्रासंगिकता' पर आयोजित किए गए गोलमेज सम्मेलन में वक्ता थे और इससे पहले ब्रेकफास्ट बैठक में भाग लिया।

- मोहाली में 26 फरवरी, 2017 को इंटरनेशनल सोसायटी फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलि. टी (आईएसईईएस) और सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड एप्लायड बायोप्रोसिंग द्वारा 'सतत ऊर्जा और पर्यावरण चुनौतियां (एसईईसी–2017)' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया।

- नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, नेपाल (नेनेप), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारतीय परिषद और नेपाल–भारत सहयोग मंच (एनबीएसएम), बीरगंज द्वारा 3–4 मार्च, 2017 को बीरगंज, नेपाल में 'नेपाल–भारत संबंधः अर्थशास्त्र विकास और सहयोग' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए संगोष्ठी में उद्घाटन भाषण दिया।

- बैंकॉक रिसर्च सेंटर, आईडीई–जेट्रो, सचिवालय द्वारा 7 मार्च 2017 को जकार्ता, इंडोनेशिया में 'नया सामान्य, एकता और विषमता' पर अनुसंधान संस्थान नेटवर्क बैठक (आरआईएनएम) पर आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 15 मार्च 2017 को नई दिल्ली में 'जैव सुरक्षा पर चरण द्वितीय क्षमता निर्माण परियोजनाः परिणाम और आगे की राह' पर आयोजित की गई कार्यशाला में 'एलएमओ का सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकनः परिणाम और आगे की राह' पर एक प्रस्तुति दी और उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया।
- पार्टनरिंग होप इन टू एक्शन (फिया) फाउंडेशन और वादा ना तोड़ो अभियान (डब्ल्यूएनटीए) द्वारा 17 मार्च 2017 को नई दिल्ली में 'लक्ष्य 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना – सहयोगियों' पर संयुक्त रूप से आयोजित की गई राष्ट्रीय मंत्रणा में 'एसडीजी लक्ष्य और प्रस्तावित राष्ट्रीय संकेतक, 2017' पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 24 मार्च 2017 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा 'स्टार्ट–अप्स को नई गति प्रदान करने के लिए नवाचार परितंत्र से लाभ उठाने' पर आयोजित किए गए 43वें एनआरडीसी मेधावी आविष्कार पुरस्कार समारोह और सम्मेलन के दौरान 'समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट–अप्स को सक्षम बनानाः राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य' पर एक सत्र की अध्यक्षता की।
- नई दिल्ली में 27 मार्च 2017 को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा भारत के विकास सहयोग से जुड़ी कैपस्टोन 10 परियोजना पर आयोजित की गई आरंभिक कार्यशाला में 'भारत के गतिशील विकास सहयोग' पर एक प्रस्तुति दी।
- नैरोबी में भारत के उच्चायोग, नैरोबी स्थित एशियाई अफ्रीकी विरासत ट्रस्ट और भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान द्वारा 28 मार्च 2017 को नैरोबी में 'कनेक्टिविटी पर दोबारा गौर कियाः भारत, केन्या और हिंद महासागर' पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए संगोष्ठी में 'विकास उन्मुख व्यापार नीतियां और सहयोगः भारत–केन्या भागीदारी के लिए नई संभावनाओं की तलाश' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. एस. के. मोहंती

- नई दिल्ली में 11 जनवरी 2017 को विदेश मंत्रालय में ब्लू इकोनॉमी फोरम पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 11 जनवरी 2017 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आयोजित ब्लू इकोनॉमी फोरम पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 16 जनवरी 2017 को नीति आयोग द्वारा 'भारत में पोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 18 जनवरी 2017 को वाणिज्य विभाग में भारत–मॉरीशस संयुक्त अध्ययन समूह पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 19 जनवरी 2017 को वाणिज्य विभाग में वाणिज्य और उद्योग पर गठित सचिवों के समूह के अंतर्गत 'व्यापार और निवेश' पर आयोजित समूह की परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 27 जनवरी 2017 को वाणिज्य विभाग में व्यापार और निवेश पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 7 फरवरी 2017 को यूएमआईएसएआरसी और दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र, पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परिचर्चा बैठक में 'क्या दक्षिण एशिया का आर्थिक प्रदर्शन दमदार है?: मजबूत क्षेत्रीय गवर्नेंस की बदौलत निरंतर क्षेत्रीय विकास संभव है' विषय पर एक संयुक्त पेपर प्रस्तुत किया।
- नई दिल्ली में 13 फरवरी, 2017 को एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आईईआरए अवार्ड 2016 की प्रथम ज्यूरी बैठक की अध्यक्षता की।
- 16 और 20 फरवरी 2017 को फिक्की द्वारा आयोजित ब्लू इकोनॉमी पर टास्कफोर्स की बैठकों में भाग लिया।
- 21 फरवरी 2017 को वाणिज्य विभाग में ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 28 फरवरी 2017 को वाणिज्य विभाग में आयोजित यूरोपीय संघ और एलएसी में व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों पर परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 20 मार्च 2017 को वाणिज्य विभाग में आयोजित 'भारत–मॉरीशस संयुक्त अध्ययन समूह' की परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

प्रो. राम उपेंद्र दास

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 6, 9, 18 और 30 जनवरी, 2017 को आयोजित भारतीय और ईएईयू एफटीए के बीच संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी) पर बैठकों में भाग लिया।

दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान (एसएआईआईए), जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका द्वारा 'अफ्रीका और जी–20: सतत विकास के लिए गठजोड़ का निर्माण' विषय पर 1–3 फरवरी 2017 को आयोजित टी20 अफ्रीका सम्मेलन में प्रो. राम उपेंद्र दास।

- 6 जनवरी, 2017 को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'आर्थिक मामलों की समिति की प्रथम समिति बैठक' में भाग लिया।
- थाईलैंड के बैंकाक में एशिया–प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनएस्कैप) द्वारा 11–12 जनवरी, 2017 को आयोजित 'एशिया–प्रशांत व्यापार समझौताः एक भावी रोडमैप' पर एपीटीए की स्थायी समिति के 50वें सत्र में और 13 जनवरी, 2017 को आयोजित एपीटीए की मंत्रिस्तरीय परिषद के चौथे सत्र में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।
- 17 जनवरी 2017 को नई दिल्ली स्थित दक्षिण कोरिया के दूतावास द्वारा आयोजित भारत–दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की बैठक में भाग लिया।
- 23 जनवरी, 2017 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रोफेसर (डॉ.) इडेसबाल्ड गोद्देइरिस, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन, बेल्जियम के साथ आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 27 जनवरी, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा व्यापार और निवेश पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 1–3 फरवरी, 2017 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान (एसएआईआईए) द्वारा टी–20 जर्मनी के सह–अध्यक्ष जर्मन विकास संस्थान/ड्यूश इंस्टीट्यूट फर एंटविकलंगस्पोलि. टिक (डीआईई) और इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी (आईएफडब्ल्यू कील) के सहयोग से 'अफ्रीका और जी–20ः सतत विकास के लिए गठजोड़ के निर्माण' पर आयोजित टी20 अफ्रीका सम्मेलन में पैनल के एक सदस्य के रूप में भाग लिया।

23–24 मार्च, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा 'सेवाओं में व्यापार सुविधा (टीएफएस)' पर आयोजित कार्यशाला में प्रो.राम उपेंद्र दास।

- 7 फरवरी, 2017 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एफटीए के अंतर्गत उत्पत्ति के नियमों पर वार्ता के तहत आयोजित एक मंथन सत्र में भाग लिया।
- 14 फरवरी, 2017 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 'व्यापार की रोजगार सृजन क्षमता' पर आयोजित एक बैठक में एक प्रस्तुति दी।
- 14 फरवरी, 2017 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 'बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच उप–क्षेत्रीय सहयोग' पर आयोजित एक प्रारंभिक बैठक में भाग लिया।
- 15 फरवरी, 2017 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्पत्ति के आरसीईपी नियमों पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली द्वारा 21 फरवरी, 2017 को 'नए बाजार नए अवसरः गंतव्य सीआईएस' पर आयोजित एक बैठक में एक प्रस्तुति दी।
- 23–26 फरवरी, 2017 को ईआरआईए, जकार्ता, इंडोनेशिया द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 'शेष एशिया के साथ पूर्वी और दक्षिण–पूर्व एशिया को एकीकृत करने के लिए एक आर्थिक केंद्र के रूप में भारत' पर एक प्रस्तुति दी।
- 28 फरवरी, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारत–नाफ्टा व्यापार संबंधों पर आयोजित एक परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 3, 9 और 27 मार्च, 2017 को ईएईयू देशों के साथ एफटीए पर आयोजित एक परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 07 मार्च, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 'संगोष्ठी से व्यापार में सुविधा' विषय पर आयोजित एक परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 10 मार्च, 2017 को एक्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली के सहयोग से भारत–अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर आयोजित 12वें सीआईआई एक्जिम बैंक सम्मेलन में पैनल के सदस्य के रूप में रहे।

- 20 मार्च, 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सेवाओं में व्यापार सुविधा (टीएफएस) पर भारत के प्रस्ताव पर आयोजित एक परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 23–24 मार्च, 2017 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा विश्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा सेवाओं में व्यापार सुविधा (टीएफएस) पर आयोजित कार्यशाला में एक संचालक (मॉडरेटर) के रूप में भाग लिया।
- 28 मार्च, 2017 को रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), नई दिल्ली द्वारा 'कनेक्टिविटी का अर्थशास्त्रः क्षेत्र से परिदृश्य' पर आयोजित 10वें आईडीएसए दक्षिण एशिया सम्मेलन के एक सत्र को संचालित किया।

प्रो. टी.सी.जेम्स

विजिटिंग फेलो

- यूरोपीय संघ के बौद्धिक संपदा कार्यालय द्वारा क्रमशः 16, 18, 20, और 21 जनवरी, 2017 को कोचीन, चेन्नई, विजयवाड़ा और बेंगलुरू में उत्पादकों, सलाहकारों और अटार्नी के लिए जीआई पर आयोजित कार्यशालाओं में भारतीय भौगोलिक संकेतक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया और भारतीय भौगोलिक संकेतकों (जीआई) के व्यवसायीकरण पर प्रस्तुति दी।
- 4–6 फरवरी, 2017 को महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम द्वारा 'वैश्वीकरण और भारत की नवाचार प्रणालीः एक रचनात्मक विनाश' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और 'उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों और अनुसंधान एवं विकास' के बारे में बताया और इसके साथ ही कुछ सत्रों की अध्यक्षता भी की।
- 6 फरवरी, 2017 को कोच्चि में 'ट्रिप्स समझौते पर एक प्रतिक्रिया के रूप में पेटेंट कार्यालयों में सुधार' के बारे में कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को संबोधित किया।
- 9 फरवरी, 2017 को सीएसआईआर एचआरडीसी, गाजियाबाद में 'आईपीआर और आरएंडडी में नैतिकता' पर सीएसआईआर के वैज्ञानिकों को संबोधित किया।
- 18 फरवरी 2017 को इंदौर में आयोजित दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- 24 फरवरी, 2017 को तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय जैव विविधता कांग्रेस 2017 में 'जैव विविधता, स्वास्थ्य और तंदरुस्ती' विषय पर आमंत्रण भाषण दिया।
- 03 मार्च 2017 को दिल्ली न्यायिक अकादमी द्वारा 'अधिनिर्णय में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के एकीकरण' पर आयोजित सम्मेलन में दिल्ली के जिला न्यायाधीशों को संबोधित किया।
- नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए भारतीय सोसायटी में 'एमएसएमई के लिए आईपीआर पर जागरूकता/संवेदनशीलता' के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 4 मार्च, 2017 को 'एमएसएमई हेतु भौगोलिक संकेतकों की गुंजाइश' विषय पर विशेष भाषण दिया।
- 17 मार्च, 2017 को पंडित बी डी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता' पर आयोजित स्वर्ण जयंती एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य भाषण दिया।
- 27–28 मार्च 2017 को 'एजेंडा 2030 के लिए आधिकारिक सांख्यिकी के परिवर्तन में तेजी लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने' पर एशिया–प्रशांत सम्मेलन में और 29 मार्च, 2017 को थाईलैंड के बैंकाक में सतत विकास पर एशिया–प्रशांत फोरम में भाग लिया। सम्मेलन में सांख्यिकी के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। एशिया–प्रशांत फोरम में नीति आयोग–आरआईएस का एक मंडप (पवेलियन) स्थापित किया गया था और एसडीजी को लेकर भारत के प्रयासों पर साहित्यिक रचना एवं अन्य प्रचार सामग्री पेश की गई तथा आगंतुकों को उपलब्ध कराई गई।

डा. के. रवि श्रीनिवास

विजिटिंग फेलो

- 1 फरवरी 2017 को कानून संकाय, यूसीएल, लंदन में 'प्रतिस्पर्धा कानून में वैश्विक वैल्यू चेन' पर आयोजित सम्मेलन में वैश्विक वैल्यू चेन, बीजों और प्रतिस्पर्धा कानून पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 मार्च 2017 को सिराड, मॉन्टेपिलर, फ्रांस में 'विकल्पों की तैयारी?ः पौधों की किस्मों/बीजों के लिए लोक और खुला स्रोत दृष्टिकोण' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया।
- 22 मार्च 2017 को सीसीएस, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू में 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियां एवं पहुंच, समानता तथा समावेशः सिद्धांत, व्यवहार और मापन से जुड़े मुद्दों' पर भाषण दिया।

डॉ. प्रियदर्शी दास

रिसर्च एसोसिएट

- 22 मार्च 2017 को चोंगयांग इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज (आरडीसीवाई), रेनमिन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, बीजिंग, चीन में वित्तीय सहयोग को सुदृढ़ करने और ब्रिक्स विकास को बढ़ावा देने पर आयोजित 2017 ब्रिक्स थिंक टैंक संगोष्ठी में 'ब्रिक्स वित्तीय सहयोगः चिन्हित क्षेत्रों और भविष्य में गुंजाइश' पर एक प्रस्तुति दी।
- 23 मार्च 2017 को दक्षिण एशिया–पश्चिम चीन सहयोग और विकास अध्ययन केंद्र, सिचुआन विश्वविद्यालय, चेंगदू, चीन में 'ब्रिक्स की संभावनाएंः ब्रिक्स फोरम में चीन–भारत सहयोग' पर एक प्रस्तुति दी।

नवीनतम प्रकाशन

रिपोर्ट

आर्थिक एकीकरण एवं विकास साझेदारियांः दक्षिणी परिप्रेक्ष्य

आरआईएस, नई दिल्ली, 2017

भारत–सिंगापुर सीईसीएः एक आकलन

आरआईएस एवं एआईसी, नई दिल्ली, 2017

हार्ट आफ एशिया एवं कनेक्टिविटी पर संगोष्ठी की रिपोर्टः कार्यवाही का सार

आरआईएस, नई दिल्ली, 2017

आरआईएस के परिचर्चा पेपर

208 **रिवर्सिंग प्री–मैच्योर डीइंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर जाब्स क्रिएशनः लेशंस फार 'मेक–इन–इंडिया' फ्रॉम एक्सपीरिएंसेज आफ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज** *द्वारा नागेश कुमार, 2017*

आरआईएस का नीतिगत पेपर

77 **इंडियन इकोनॉमी एंड डिमोनेटाइजेशनः वे फारवर्ड,** *द्वारा सुभोमय भट्टाचार्जी, जनवरी 2017*

पत्रिका

एशियन बायोटेक्नोलाजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू

खंड 18 संख्या 3, नवंबर 2016

आरआईएस डायरी

खंड 13 संख्या 1, जनवरी 2017

ब्लू इकोनॉमी पर नीतिगत पेपर

अनलीजिंग द पोर्टेंशियल आफ ब्लू इकोनॉमी,

द्वारा एस.के.मोहंती, प्रियदर्शी दास और आस्था गुप्ता, 2017, आरआईएस, नई दिल्ली

आरआईएस संकाय द्वारा बाह्य प्रकाशनों में योगदान

दास, राम उपेंद्र। 2016. 'मध्य एशियाई गणराज्य'श्री जूंग–वान चो और श्री राजन सुदेश रत्न (संपादक): *एशिया–प्रशांत व्यापार समझौताः दक्षिण–दक्षिण क्षेत्रीय एकीकरण और सततविकास* को प्रोत्साहन, बैंकाकः यूएनएस्कैप।

दास, राम उपेंद्र। 2016. 'एशिया–प्रशांत व्यापारसमझौताः भविष्य का रोडमैप' श्री जूंग–वान चो और श्री राजन सुदेश रत्न (संपादक): *एशिया–प्रशांत व्यापार समझौताः दक्षिण–दक्षिण क्षेत्रीय एकीकरण और सतत विकास को बढ़ावा,* बैंकाकः यूएनएस्कैप।

दास, राम उपेंद्र और अनूप कुमार झा। 2017. 'भारत,रूस 2017 में भू–राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे।' *रूस एंड इंडिया रिपोर्ट*। रूस बेयांड द हेडलाइंस, 23 जनवरी

दास, राम उपेंद्र। 2017. ' सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे की ओर सुसंगत जी20 नीतियां' जी20 *इनसाइट्स,* 10 मार्च।

डे, प्रबीर। 2017. 'बिम्सटेक और आईओआरए के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीके', योगेंद्र कुमार (संपादक) *कहां है भारतीय महासागर समुद्री आदेश? नरेंद्र मोदी के सागर भाषण पर संगोष्ठी में योगदान,* नॉलेज वर्ल्ड, नई दिल्ली

डे, प्रबीर और श्रेया पैन। 2017. *भारत और मंगोलिया के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत करनाः कार्य और अवसर*। नॉलेज वर्ल्ड , नई दिल्ली

श्रीनिवास, के. रवि। 2017. 'विज्ञान में सार्वजनिक सहभागिता क्यों मायने रखती है।' *जैव प्रौद्योगिकी में रुझान,* खंड 35 अंक 4 अप्रैल।

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाषः 91–11–24682177–80
फैक्सः 91–11–24682173–74 ई–मेलः dgoffice@ris.org.in
वेबसाइटः http://www.ris.org.in

Follow us on:
www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबंध संपादकः तीश मल्होत्रा